



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1847]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2010/भाद्र 17, 1932

No. 1847]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2010/BHADRA 17, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुम्बई, 8 जनवरी, 2010

का.आ. 2192(अ).—प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 29ए के अन्तर्गत भारत सरकार की दिनांक 1 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. 183(अ) द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक—

यह मानते हुए कि संपूर्ण भारत में प्रतिभूतियों के अवांछनीय सट्टे को रोकना आवश्यक है, एतद्द्वारा यह घोषणा करता है कि—

(क) उक्त अधिनियम के क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति,

1. उक्त अधिनियम, संबंधित शेयर बाजार के नियमों, विनियमों तथा उपविधियों के अंतर्गत अनुमत हाज़िर सुपुर्दगी संविदा अथवा मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में ट्रेड की जाने वाली ऐसी अन्य संविदाओं को छोड़कर सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण से संबंधित प्रतिभूतियों तथा मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों की विक्री अथवा खरीद के लिए संविदा नहीं करेगा:

- (i) बशर्ते कि संविदाएं ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों में और निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की गई ऐसी शर्तों के अनुसार, जिसमें वह आधार भी शामिल हैं जिसके अनुसार ऐसी संविदाएं निपटाई जाएंगी, "यदा जारी आधार" पर की जा सकती हैं :

(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक,

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत प्राथमिक व्यापारी

(ग) इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विशेषरूप से अनुमत कोई अन्य व्यक्ति।

- (ii) बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा सभी सरकारी प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा संविदाएं की जाएं:

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता रखने वाला कोई व्यक्ति, अथवा

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत कोई अनुसूचित बैंक अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कंपनियों से इतर) अथवा राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत कोई आवासीय वित्त कंपनी, अथवा सेबी में पंजीकृत कोई म्यूचुअल फंड कंपनी, अथवा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण में पंजीकृत कोई बीमा कंपनी जिसका किसी ऐसे व्यक्ति के पास गिल्ट खाता हो, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में सीएसजीएल खाता रखने की अनुमति दी हो, अथवा

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से गिल्ट खाता रखने वाला ऐसा कोई अन्य व्यक्ति

अथवा जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में सीएसजीएल खाता रखने की अनुमति दी हो।

(iii) बशर्ते कि कोई भी हाज़िर वायदा करार दो ऐसे व्यक्तियों के बीच न किया जाए जिनके एक ही व्यक्ति के पास गिल्ट खाते हों जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में सीएसजीएल खाता हो।

(iv) बशर्ते यह भी कि कोई ऐसा हाज़िर वायदा करार भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में एसजीएल खाता रखने वाले किसी व्यक्ति का अपने पास ही गिल्ट खाता रखने वाले दूसरे व्यक्ति के साथ न किया जाए।

(v) बशर्ते यह भी कि सभी हाज़िर वायदा करार भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में रखे एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अनुसरण में निपटाए जाएंगे।

(vi) बशर्ते यह भी कि संविदा की शर्तों के अनुसार संविदा की समाप्ति तक बकाया तैयार वायदा संविदाएं बनी रहेंगी।

2. बांडों, डिबेंचरों, डिबेंचर शेयरों, प्रतिभूतिकृत ऋण तथा किसी व्यक्ति अथवा केंद्र अथवा राज्य के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगमित निकाय सहित, द्वारा जारी की गई अन्य ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं नहीं करेगा:

बशर्ते कि हाज़िर वायदा करार विशिष्ट रेटिंग के कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा की जाए :

(क) अनुसूचित बैंक, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र बैंक (एलएबी) शामिल नहीं हैं

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत कोई प्राथमिक व्यापारी

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित किए अनुसार सरकारी कंपनियों के अतिरिक्त)

(घ) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के अंतर्गत स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक

(ङ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम, 1981 (1981 का 68) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

(च) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक

(छ) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(ज) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में विशिष्ट रूप से अनुमत और कोई व्यक्ति।

(ख) प्रस्तावित स्टॉक एक्सचेंजों पर ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट की गई संविदाएं निम्नानुसार की जाएंगी :

(i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा उपविधियों अथवा उक्त अधिनियमों के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) के अंतर्गत अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएंगी।

(iii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

स्पष्टीकरण :

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए:

(i) "अनुसूचित बैंक" से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी बैंक से है।

(ii) "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी" से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (1) में यथा परिभाषित कंपनी से है।

(iii) "म्यूच्युअल फंड" से तात्पर्य ऐसा फंड जो सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (म्यूच्युअल फंड) विनियमावली, 1996 के नियम 2 के खण्ड (क्यू) में यथा परिभाषित है।

(iv) "कांस्टीट्यूट सविस्डियरी जनरल लेजर (सीएसजीएल) एकाउंट" से तात्पर्य भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत किसी बैंक अथवा किसी व्यक्ति द्वारा उसके ग्राहकों की ओर से सरकारी प्रतिभूतियां धारण करने के प्रयोजन से भारतीय रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों में रखे गए सविस्डियरी जनरल लेजर एकाउंट से है।

(v) "गिल्ट एकाउंट" से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में सीएसजीएल खाता खोलने और रखने के लिए अनुमत किसी बैंक अथवा किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति द्वारा खोला और रखा गया प्रतिभूति खाता है।

(vi) "यदा जारी" आधार पर की गई सविदाओं से तात्पर्य कोई भी सरकारी प्रतिभूति जारी करने की अधिसूचना जारी होने के बाद किन्तु उसके वास्तव में जारी होने से पहले की गई सविदाएं।

(vii) "कार्पोरेट ऋण प्रतिभूति" से तात्पर्य अपरिवर्तनीय उधार प्रतिभूतियां जो ऋणग्रस्तता का सृजन करती हैं अथवा उसकी पहचान करती हैं जिसमें डिबेंचर, बॉण्ड केन्द्र अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत अथवा उसके द्वारा गठित किसी कंपनी अथवा निगमित निकाय की ऐसी अन्य प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे वे कंपनी अथवा निगमित निकाय की आस्तियों पर प्रभार बना रही हों अथवा नहीं लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट तथा सरकार अथवा ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जारी उधार आस्तियाँ, प्रतिभूति रसीदें तथा प्रतिभूतिकृत उधार लिखत इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

(viii) प्रतिभूति रसीद से तात्पर्य वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 के खण्ड (जेडजी) में परिभाषित प्रतिभूति है।

(ix) प्रतिभूतिकृत उधार लिखतों से तात्पर्य प्रतिभूति करार (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खण्ड (एच) के उप-खण्ड (आईई) के संदर्भ में उसी स्वरूप की प्रतिभूतियाँ हैं।

यह अधिसूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल, 2006 को जारी अधिसूचना सं. का.आ. 551(अ) का अधिक्रमण करते हुए जारी की जा रही है।

[आंशिकप्रवि. सं. 06/2009-10/फा. सं. 1/8/एस.एम/2010]

एच. आर. खान, कार्यपालक निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2010

S.O. 2192(E).— In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India under Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) vide Government of India Notification No. 183(E) dated 1st March, 2000, issued under Section 29A of the said Act, the Reserve Bank of India—

being of the opinion that it is necessary to prevent undesirable speculation in securities in the whole of India, hereby declares that—

(A) no person in the territory to which that Act extends, shall, enter into any—

(1) contract for the sale or purchase of Government securities, gold related securities and money market securities other than spot delivery contracts or such other contracts traded on a recognized stock exchange, as is permissible under the said Act, rules and bye-laws of such stock exchange.

(i) Provided that contracts may be entered into on 'when issued basis' in such Government securities and in accordance with such terms and conditions, including the basis on which such contracts may be settled, as may be specified in this regard by the Reserve Bank of India by the following persons —

(a) a scheduled commercial bank

(b) a Primary Dealer registered with the Reserve Bank of India

(c) any other person specifically permitted in this regard by Reserve Bank of India,

(ii) Provided that ready forward contracts may be entered into in all Government securities, in accordance with the terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank of India, by the following persons—

(a) any person holding a Subsidiary General Ledger account with the Public Debt Office of the Reserve Bank of India;

(b) a scheduled bank or a non-banking financial company registered with Reserve Bank of India (other than Government Companies as defined in Section 617 of the Companies Act, 1956) or a housing finance company registered with National Housing Bank, or a mutual fund registered with Securities and Exchange Board of India, or an insurance company registered with Insurance Regulatory and Development Authority, holding a Gilt account with any person permitted by Reserve Bank of India to maintain Constituent Subsidiary General Ledger account with Public Debt Office of the Reserve Bank of India; or

(c) any other person specifically permitted by Reserve Bank of India, holding a Gilt account with any person permitted by Reserve Bank of India to maintain Constituent Subsidiary General Ledger account with Public Debt Office of the Reserve Bank of India.

(iii) Provided further that no ready forward contracts may be entered into between two persons both maintaining Gilt accounts with same person maintaining Constituent

Subsidiary General Ledger account with the Public Debt Office of the Reserve Bank of India.

(iv) Provided further that no ready forward contracts may be entered into between a person maintaining Subsidiary General Ledger account with Public Debt Office of the Reserve Bank of India with another person maintaining a Gilt account with itself.

(v) Provided further that all ready forward contracts shall be settled through Subsidiary General Ledger account or a Constituent Subsidiary General Ledger account maintained with the Public Debt Office of Reserve Bank of India, in accordance with the terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank of India.

(vi) Provided further that the outstanding ready forward contracts shall continue till termination of the contracts as per the contractual terms :

(2) Ready forward contracts in bonds, debentures, debenture stock, securitised debt, and other debt securities issued by any person including any body corporate established by or under a Central or State Act :

Provided that ready forward contracts may be entered into in corporate debt securities of specified rating in accordance with the terms and conditions as may be specified by the Reserve Bank of India by the following persons—

- (a) a scheduled commercial bank excluding Regional Rural Banks (RRBs) and Local Area Banks (LABs);
- (b) a Primary Dealer registered with the Reserve Bank of India;
- (c) a non-banking financial company registered with the Reserve Bank of India (other than Government companies as defined in section 617 of the Companies Act, 1956);
- (d) Export-Import Bank of India established under the Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981);
- (e) National Bank for Agriculture and Rural Development established under section 3 of the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1981 (68 of 1981);
- (f) National Housing Bank established under section 3 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987);
- (g) Small Industries Development Bank of India established under section 3 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);
- (h) any other person specifically permitted in this regard by the Reserve Bank of India.

(B) the contracts specified in clause (A) above, entered into on the recognized stock exchanges, shall be entered in accordance with—

- (a) the rules or regulations or the bye-laws made under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the directions issued by the Securities and Exchange Board of India under the said Acts;
- (b) the rules made or guidelines or directions issued under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) or the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) or the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) by the Reserve Bank of India; and
- (c) the provisions contained in the notifications issued by the Reserve Bank of India under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

Explanation :

For the purpose of this notification—

- I. "scheduled bank" means a bank included in the second schedule of Reserve Bank of India Act, 1934.
- II. "non-banking financial company" means a company as defined in clause (1) of Section 45-1 of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- III. "mutual fund" means a fund as defined in clause (q) of the Regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996.
- IV. "Constituent Subsidiary General Ledger account" means a Subsidiary General Ledger account opened and maintained with the Public Debt Office of the Reserve Bank of India, by a bank or any other person permitted by the Reserve Bank of India, for the purpose of holding Government securities on behalf of its constituents.
- V. "Gilt account" means a securities account opened and maintained by any person with a bank or any other person permitted by the Reserve Bank of India to open and maintain Constituent Subsidiary General Ledger account with the Public Debt Office of the Reserve Bank of India.
- VI. Entering into contracts on 'when issued' basis means entering into contracts after the notification of issue of any Government security but before the actual issue thereof.
- VII. "corporate debt securities" means "non-convertible debt securities, which create or acknowledge indebtedness, including debentures, bonds and such other securities of a company or a body corporate constituted by or under a Central or State Act, whether constituting a charge on the assets of the company or body

corporate or not, but does not include debt securities issued by Government or such other persons as may be specified by the Reserve Bank, security receipts and securitized debt instruments”.

VIII. “security receipt” means a security as defined in clause (zg) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002).

IX. “securitized debt instruments” means securities of the nature referred to in sub-clause (ie) of clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

This notification is issued by Reserve Bank of India, in supersession of the notification No. S.O. 551 (E), dated April 17, 2006 issued by it.

[IDMD No. 06/2009-10/F. No. 1/8/SM/2010]

H. R. KHAN, Executive Director

352761/10-2